Fighting Fraud thru' Training

The Forerunner

A Newsletter of RTI, Nagpur, Indian Audit & Accounts Department

Nineteenth Issue | Oct. '15 - Mar. '16 | 2016

प्रधान निदेशक के पटल से

इस प्रशिक्षण संस्था को वर्ष 2015-16 से मुख्यालय ने Transfer Pricing की लेखापरीक्षा के लिए विशेष दर्जा दिया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जाने की Transfer Pricing है क्या।

औद्योगिक क्रांति ने बड़े उद्योगों को जन्म दिया क्योंकि अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी। इन विशाल उद्योगों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक उद्योग/कंपनी ने विभिन्न कार्यानुसार खंडों का निर्माण किया जैसे की उत्पादन खंड, खरीदी, बिक्री, लेखा इत्यादी। हर खंड, जैसे की उत्पादन खंड वस्तु का निर्माण कर दूसरे खंड को स्थानांतरित कर देता है और साथ ही लागत निर्माण खर्च सूचित करता है, जिससे बिक्री मूल्य निर्धारित की जा सके। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है की इस प्रक्रिया में केवल स्थानांतरण होता है, असली ग्राहक को बिक्री नहीं। अगर इसी वस्तु को बाहरी संस्था/व्यक्ति को बेचा जाए तो इसमे लाभ तत्व को जोड़कर बेचा जाता है और यह बिक्री मूल्य कहलाता है।

ग्राहक बढ़ने के कारण कंपनियों को स्थान की कमी होने लगी और इस स्थिति से निपटने के लिए खंडो को अलग-अलग जगह पर स्थापित करना पडा। कंपनियों ने सुविधानुसार, जहाँ लागत मूल्य कम से कम हो ऐसे स्थानों पर खंड स्थापित किए जैसे उत्पादन खंड या कारखाने वहाँ लगाए गए जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता सुगमता से हो। आगे इसी कड़ी में खंडो का स्थान लिया सहायक कंपनियों ने जिसे Transfer Pricing की भाषा में Associate Enterprise कहा जाता है। इन सहायक कंपनी द्वारा निर्मित वस्तु को मुख्य कंपनी को उसी मूल्य पर स्थानांतरित करनी होती है जिस मूल्य पर वह बाहरी संस्था/व्यक्ति को बेचती है। इसे Arm's Length Price कहा जाता है। Arm's Length Price की यही विशेषता है की इसमे स्थानांतरित मूल्य और बिक्री मूल्य एक ही होता है और इसे वैध भी माना जाता है। यह इसलिए है क्योंकी कर गणना करते समय इसी Arm's Length Price की मान्यता है और इसे प्रत्येक कंपनी पर समान रूप से लागू होता है। क्या प्रत्येक कंपनी Arm's Length Price को पूरी तरह से लागू करती है, इसका उत्तर निश्चित ही नहीं है। इसके पीछे कारण हैं कर बचाना, कंपनीयाँ अपनी आय बढ़ाने के लिए कर बचाती है लेकिन इसका असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। इस समस्या से केवल हमारा ही देश नहीं अपितु पूरी दुनियाँ ही इस से जूझ रही है। यह समस्या और गहराई 'Tax Haven' देशों के कारण।

चूंकि आज के दौर में 'Tax Haven' याने 'करो का स्वर्ग' वाले बहुत से देश है जहाँ बहुत से कर या तो होते नहीं है जैसे की आयकर या उनकी दरें बहुत कम होती है और अधिकांश बड़ी कंपनियों की सहायक कंपनी इन्ही देशों में स्थित होती है, ऐसे में किसी भी वस्तु का लागत मूल्यांकन (Costing) बहुत ही कठिन होता है। फिर जब कोई मुख्य कंपनी अपनी सहायक कंपनी जो इस करो के स्वर्ग में स्थित है उससे वस्तु की खरीदी दर्शाती है तब उसके मूल्य में सत्यता की कमी साफ दिखाई देती है। यह किसी भी कंपनी के financial statements से जाना जा सकता है।

इस समस्या के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) आगे आई और इसने इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। विश्व के अधिकांश देश इस संस्थान के सदस्य है जिसमे भारत भी एक है। कंपनियाँ जब स्थानांतरित मूल्य ठीक घोषित नहीं करती तब सही मूल्य जानने के लिए OECD द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशें का सहारा लिया जाता है जिसे Transfer Pricing Methods के नाम से जाना जाता है। Transfer Pricing Methods मुख्यतः पाँच है जो निम्नलिखित है: Comparable Uncontrolled Pricing (CUP), Resale Price Method (RPM), Cost Plus Method (CPM), Profit Split Method (PSM), Transactional Net Margin Method (TNMM), यह पाँचों Transfer Pricing Methods विभिन्न स्थितियों में लागू होते है जैसे तैयार उत्पाद का स्थानांतरण, सेवा का समावेश, intangibles कर्ज या वित्त का समावेश के मामलों में CUP तरीका उपयोग किया जाता है।

चूंकि इस मामले में बड़ी कंपनियों का समावेश है जिनका कारोबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, इसलिए इस विषय का पूर्ण रूप से उचित निराकरण हो गया है ऐसा अभी कहाँ नहीं जा सकता। लेकिन पूरा विश्व इस मामले में साथ खड़ा है इसलिए संभव है की भविष्य में इस समस्या का पूर्ण निराकरण निकले। कब तक यह तो आनेवाला समय ही बता पाएंगा।

अंत में मैं माह फरवरी 2016 में आयोजित क्षेत्रीय समिती के सदस्यों को बैठक में शामिल होने तथा उसे सफल बनाने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा।

जयदीप शाह
प्रधान निदेशक

In this Issue

- Memorable Moments Unfolded
- Impact of Training
- Education Column
  - Understanding Non Tax Revenue
- Evaluation of Training
- Our Toppers
- Faculty Column
  - Treasury Inspection (contd.)
  - Public Sector Enterprises in India : Role, Growth and Problems
- Audit Column
  - Auditing the Government Response to Climate Change
  - इलेक्ट्रानिक वेस्ट का निपटान

Our Products

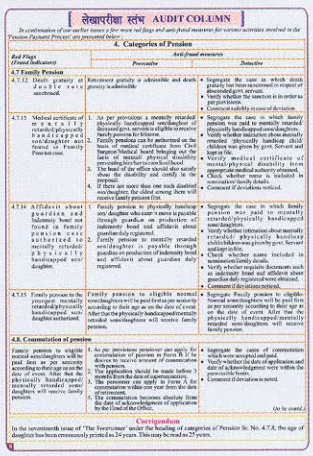
लेखापरीक्षा स्तंभ AUDIT COLUMN

4. Categories of Pension

The Forerunner

Eighteenth Issue of News Letter

The Mandate

Headquarter has declared this Institute as a Knowledge Resource Centre in 'Audit of Fraud, Fraud Detection Techniques & Forensic Audit' in October 2003 and "Central Revenue Audit including Transfer Pricing" in April 2015 with a mandate to act as a repository of information on the subject through developing quality reading material, case studies (National and International), research papers and database of expert faculty and media reports. Significant developments in the matter are also to be reported through a newsletter for information to the user offices and sister Institutes.